मध्य प्रदेश में स्थापित लघु उद्योग

3950. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इस समय जिले-वार कितने लघु उद्योग स्थापित किए गए हैं,

(ख) इन उद्योगों में कितने-कितने व्यक्ति दैनिक और मासिक वेतन पर कार्यरत हैं,

(ग) इन उद्योगों के उत्पादों के विपणन की क्या व्यवस्था की गई है,

(घ) क्या इनमें से कुछ उद्योग रुग्ण होते जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) उद्योग आयुक्त, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31-12-1992 को लघु उद्योग विकास संगठन (सीडी) के क्षेत्राधिकार में आने वाली 1,06,638 लघु इकाइयों को स्थायी आधार पर पंजीकृत किया गया था । इन इकाइयों के जिले-वार ब्यौरे विवरण—I में दिये गये हैं ।

(ख) इन उद्योगों में मासिक और दैनिक मजदूरी के आधार पर इस समय कार्य कर रहे कर्मचारियों के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, 1989—91 के दौरान विकास आयुक्त (लघु उद्योग) द्वारा की गई लघु औद्योगिक इकाइयों की द्वितीय अखिल भारतीय गणना की रिपोर्ट में दी गई सूचना के अनुसार आंकड़े विवरण—II में दिये गये हैं जिसका आधार वर्ष 1987-88 है ।

(ग) विपणन सुविधा एक उद्यमिता कार्य है । तथापि, लघु उद्योग के कार्य आधार पर विचार करते हुए 409 मदों को केन्द्र सरकारी भंडार खरीद कार्यक्रम के तहत खरीदने के लिए आरक्षित किया गया है और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों को एक ही स्थान पर पंजीकरण योजना के तहत निम्नलिखित विशेष सुविधाएं दी गयीं हैं :—

(1) निःशुल्क टेंडर सेट जारी करना ।

(2) बयाना राशि के भुगतान की छूट ।

(3) जिस वार्षिक सीमा तक इकाई पंजीकृत है उतनी राशि तक सिक्यूरिटी डिपाजिट की छूट ।

(4) बड़ी औद्योगिक इकाइयों के कोटेशनों की तुलना में गुणदोष के आधार पर 15% तक मूल्य वरीयता ।

मध्य प्रदेश सरकार सहित राज्य/केन्द्र शासित सरकारें अपने-अपने नीतिगत उपायों के अनुसार राज्य खरीद कार्यक्रम के तहत उनके उत्पादों को बेचने के लिए लघु औद्योगिक इकाइयों की सहायता करते हैं ।

(घ) जी, हां । भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश में मार्च, 1992 के अंत तक 22,333 रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयां थीं ।

(ङ) राज्य स्तरीय अंतर-संस्थागत समिति और राज्य स्तरीय पुनर्स्थापना समिति के माध्यम से जीव्यक्षम रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास के लिए नियमित आधार पर उपाय किये जा रहे हैं । जीव्यक्षम रुग्ण इकाइयों की पुनर्स्थापना में बैंकों द्वारा भी नियमित आधार पर मदद की जा रही है । राष्ट्रीय ईक्विटी निधि से संभावित जीव्यक्षम रुग्ण लघु औद्योगिक एककों को जिनकी परियोजना लागत 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है, को 1% वार्षिक सामान्य सेवा प्रभार पर 1,50,000 रुपये तक की दीर्घावधि ईक्विटी सहायता के रूप में वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है । लघु औद्योगिक इकाइयों में व्याप्त रुग्णता की समस्याओं का तत्काल समाधान करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के लिए कार्यवाही करने हेतु मुख्य-मुख्य क्षेत्रीय केन्द्रों में प्रकोष्ठ स्थापित करें और तकनीकी कार्मिकों सहित विशेषज्ञों की सेवा मुहैया करायें ।

विवरण : I

मध्य प्रदेश में 31-12-92 को पंजीकृत सीडी इकाइयों की जिलेवार समेकित संख्या का विवरण ।

क्र० सं०	जिले का नाम	31-12-92 को इकाइयों की समेकित संख्या
1	2	3
1.	खंडवा	3371
2.	खड़गांव	8168
3.	झाबुआ	276
4.	इंदौर	5962
5.	धार	1994
6.	पिथमपुर	349
7.	देवास	*2460
8.	उज्जैन	3983
9.	मंदसौर	2274

1	2	3
10.	शाजापुर	3430
11.	रतलाम	2572
12.	सिहोर	*2013
13.	भोपाल	4503
14.	राजगढ़	*2821
15.	रायसेन	*2057
16.	मंदसौर	*147
17.	विदिशा	3159
18.	बेतुल	*2642
19.	होशंगाबाद	2402
20.	रायपुर	*10448
21.	दुर्ग	8603
22.	राजनंदगांव	*2855
23.	जगदलपुर	558
24.	बिलासपुर	1290
25.	रायगढ़	7475
26.	अम्बिकापुर	4481
27.	नरसिंगपुर	*2268
28.	मांडला	5064
29.	सिवानी	1635
30.	जबलपुर	12061
31.	बालाघाट	2185
32.	छिन्दवाड़ा	*3692
33.	भिन्ड	*5487
34.	मुरैना	4271
35.	गुना	2499
36.	ग्वालियर	3599
37.	दतिया	*1410
38.	मालनपुर	*206
39.	शिवपुरी	*2841
40.	रीवा	683
41.	सतना	3906
42.	सिधी	1765
43.	शहडोल	679
44.	सागर	3559
45.	छतरपुर	*2873
46.	टिकमगढ़	*1720
47.	पन्ना	18
48.	दमोह	1949

*ये आंकड़े अनंतिम हैं ।

नोट : जिलों के नाम राज्य उद्योग निदेशालयों द्वारा दिये गये हैं ।

विवरण II

कर्मचारियों का जिलेवार वर्गीकरण--1987-88

क्र. सं०	जिला	कर्मचारियों का वर्गीकरण (संख्या)			
		सीधे भर्ती/ नियमित	दिहाड़ी/ ठके पर	कुल कर्मचारी	स्वयं नियोजित
1	2	3	4	5	6
1.	बालाघाट	1606	1983	3589	1017
2.	बस्तर	2531	1274	3805	1873
3.	बेतुल	1080	614	1694	853
4.	भिन्ड	2621	495	3116	1846
5.	बिलासपुर	1782	1849	3631	1167
6.	छतरपुर	2239	902	3141	1919
7.	छिन्दवाड़ा	1954	1522	3476	1830
8.	दमोह	560	373	933	491
9.	दतिया	551	126	677	443
10.	देवास	1667	182	1849	988
11.	धार	1942	1604	3546	1042
12.	दुर्ग	3512	3681	7193	1818

1	2	3	4	5	6
13.	गुना	1140	811	1951	986
14.	ग्वालियर	2121	976	3097	977
15.	होशंगाबाद	2621	2443	5064	1859
16.	इंदौर	8860	1084	9944	1884
17.	जबलपुर	4523	5518	10041	2422
18.	झबुआ	736	827	1563	561
19.	मांडला	1467	881	2348	1292
20.	मंदसौर	3771	804	4575	2086
21.	मुरैना	1030	249	279	443
22.	नरसिंघपुर	1288	713	2001	1008
23.	खण्डवा (पूर्व निमार)	2415	549	2964	1465
24.	खारगदम (प० निमार)	3698	1130	4828	3101
25.	पन्ना	2040	286	1326	845
26.	रायगढ़	4011	1276	5287	3074
27.	रायपुर	5329	4690	10019	2884
28.	रायसेन	1845	1018	2863	996
29.	राजगढ़	1814	41	1855	986
30.	रतलाम	1538	1422	2960	971
31.	रीवा	1891	1372	3263	1501
32.	सागर	2276	1592	3868	1609
33.	सतना	3658	2217	5875	2339
34.	सिहोर	910	1224	2134	863
35.	सिवनी	1686	712	2398	1252
36.	शाहडोल	1198	4325	5523	1183
37.	शाजापुर	1236	699	1935	1071
38.	शिवपुरी	954	524	1478	780
39.	सिधी	422	395	817	384
40.	अंबिकापुर (सरगुजा)	2029	594	2623	1715
41.	टिकमगढ़	986	518	1504	821
42.	उज्जैन	2034	1416	3450	1727
43.	विदिशा	1077	305	1382	660
44.	भोपाल	5135	2327	7462	1471
45.	राजनंदगांव	1911	2570	4481	1330
	कुल	98695	60113	158808	61833

स्रोत : राज्य/संघ शासित उद्योग निदेशालयों में पंजीकृत लघु उद्योगों की द्वितीय अखिल भारतीय गणना ।

Setting up of Industrial Technological Parks

3951. SHRI SATISH PRADHAN : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the number of Industrial Technological Parks proposed by Government, State-wise; and

(b) what are the parameters for deciding the location of Industrial Technological Park ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI) : (a) There is no proposal with the Government for setting up of Industrial Technological Parks in the Country.

(b) Do not arise.